have already been provided safe drinking water from this scheme. Remaining villages are likely to be covered by the end of June, 1992.

(e) No financial assistance is given to the affected villagers. Safe drinking water facilities are provided free of cost either through alternative safe sources or through defluoridation plants.

विदेशी सहायता वाली पेयजल परियोजनायें

1313. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितनी पेय जल परियोजनाएं विदेशी कर्ज/सहायता से चल रही है ; और

(ख) इन परियोजनाओं से कितने व्यक्ति, लाभान्वित हो रहे हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री उत्तमभाई एच पटेल) : (क) आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तमिलनाडु, और उत्तर प्रदेश राज्यों में इंग्लैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, जर्मनी और विश्व बैंक की सहायता से 32 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं ।

(ख) इन परियोजनाओं के माध्यम से लाभान्वित हो रहे लोगों के बारे में सूचना फिलहाल केन्द्रीय सरकार के स्तर पर नहीं रखी जाती है । इस बारे में सूचना एकत्र की जा रही है ।

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में शीत भण्डारण सुविधा

1314. **कुमारी आलिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फेल, सब्जियां और बाजरे के लिए पर्याप्त शीत भण्डारण सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) और (ख) सरकार को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फल, सब्जियों और बाजरे के लिए शीत भंडारण सुविधाओं की अपर्याप्तता के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

मध्य प्रदेश में 116 शीत भण्डागार हैं जिनकी कुल भंडारण क्षमता 222599 मीटरी टन है ।

उत्तर प्रदेश में राज्य शीत भण्डागार अधिनियम के अन्तर्गत शीत भाण्डागारों का विनियमन किया जाता है । उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार, राज्य में 906 शीत भाण्डागार हैं जिनकी कुल भण्डारण क्षमता 3554310 मीटरी टन है ।

Issue of Pass-Book to Agricultural Land-Holders/Tillers

1315. SHRI SHABBIR AHMED SALARIA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that pass-books have not been issued to agricultural land-holders and tenants of agricultural land in J & K although the same have been got printed ;

(b) whether it is a fact that such pass-books have been issued in many other States ; and

(c) if so, what steps Government propose to take in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI G. VENKAT SWAMY) : (a) The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House.